टी. ए. हामिद

बनाम

एम. विश्वनाथन

(2001 की सिविल अपील सं. 8422)

21 फरवरी, 2008

(ए. के. माथुर और अल्टमास कबीर, जे. जे.)

उच्च न्यायालय-पूर्ण रूप से कानून के प्रश्न का संदर्भ पीठ-प्रश्न का उत्तर देने वाली पूर्ण पीठ का अधिकार क्षेत्र और गुण-दोष के आधार पर स्वयं संशोधन का निर्णय लेना-आयोजितः पूर्ण पीठ के पास पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था पुनरीक्षण याचिका को पूर्ण पीठ के पास नहीं भेजा गया था निर्णय-चूंकि, केवल पूर्ण पीठ के लिए संदर्भ दिया गया था, उसे उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था जो उसे भेजा गया था। पुनरीक्षण पर निर्णय लेने के लिए डिवीजन बेंच को मामला गुण-दोष पर याचिका-पूर्ण पीठ का आदेश गुण-दोष पर सिविल पुनरीक्षण याचिका सही नहीं थी-पुनरीक्षण याचिका पुनर्जीवित की जाएगी और सुनवाई के लिए पहले रखी जाएगी। एक खंड पीठ, जो इसका निपटारा करेगी दोनों पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार-अभ्यास करें और प्रक्रिया-उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का अधिकार क्षेत्र इसके लिए कानून के प्रश्न के संदर्भ का मामला-केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम - एस. 11 (17)।

केरल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय बनाम रामबल कंपनी और अन्य (2006) 6 एस. सी. सी. 258, और केशो नाथ खुराना वी. भारत संघ और अन्य 1981 (पूरक) एससीसी 38-पर निर्भर

सिविल न्याय निर्णयः सिविल अपील सं. 8422/2001

(केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के सी.आर.पी.सं. 2006/1999 के साथ सिविल अपील नं. 1817 2004 में पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांकित 8/8/2000 से)

मालिनी पोदुवल और निशे राजन शोंकर (मेसर्स के लिए)। टी. टी. के दीपक एंड कंपनी) अपीलार्थी के लिए।

प्रतिवादी की ओर से सुब्रमण्यम प्रसाद और के. राजीव।

न्यायालय का आदेश दिया गयाः

सी.ए.संख्या 8422/2001

1. उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना। पक्षों के विद्वान वकील का कहना है कि पक्षों ने मामले में समझौता कर लिया है और इसलिए, वर्तमान अपील निरर्थक हो गई है।

2. अपील निरर्थक होने के कारण खारिज की जाती है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

सी.ए. संख्या 1817/2004

3. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील सीआरपी संख्या 234/1997 में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 31.1.2003 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान पूर्ण पीठ ने संदर्भित प्रश्न का उत्तर दिया है डिवीजन बेंच द्वारा इस पर विचार किया गया और संदर्भित प्रश्न का उत्तर देते समय, पूर्ण बेंच ने स्वयं मामले को गुण-दोष के आधार पर तय किया। यहां अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि केशो नाथ खुराना बनाम के मद्देनजर।

भारत संघ और अन्य 1981 (सप्प) एससीसी 38 और केरल राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय बनाम रामबल कंपनी और अन्य (2006) 6 एससीसी 258, पूर्ण पीठ को मामले की योग्यता पर नहीं जाना चाहिए था और पूर्ण पीठ को संदर्भ का जवाब देने के बाद मामले को सिविल पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने के लिए डिवीजन बेंच को वापस भेज देना चाहिए था।

4. वर्तमान अपील के निपटान के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि केरला उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा एक संदर्भ दिया गया था, जो इस प्रकार है-

"क्या मृत किरायेदार के कानूनी उत्तराधिकारी धारा की सुरक्षा के हकदार हैं केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम की धारा 11(17)?"

5. इस संदर्भ का उत्तर पूर्ण पीठ द्वारा आक्षेपित आदेश के पैरा 18 में निम्नलिखित शब्दों में दिया गया था,

"कानूनी उत्तराधिकारियो/किरायेदारों को धारा 11(17) के तहत लाभ को सही कानून निर्धारित करने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

आक्षेपित आदेश के पैरा 19 में विद्वान पूर्ण पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों से गुण-दोष के आधार पर दलीलें आगे बढ़ाने को कहा क्योंकि कार्यवाही लगभग एक दशक पहले शुरू की गई थी और दोनों पक्षों के वकीलों से पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करने के लिए कहा और तदनुसार दलीलें सुनी गईं। पुनरीक्षण याचिका के गुण-दोष के आधार पर भी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता-किरायेदार को छह महीने के भीतर कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया और अपीलकर्ता को इस आशय का एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया।

6. पूर्ण पीठ के उक्त आदेश दिनांक 31.01.2003 से व्यथित होकर, विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि पूर्ण पीठ को गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण याचिका का निपटारा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब न्यायालय ने पक्षकारों के वकीलों को गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया, तो उनके पास मामले के गुण-दोष के आधार पर न्यायालय को संबोधित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालाँकि, उन्होंने इसे निर्धारित कानून के मद्देनजर प्रस्तुत किया । इस न्यायालय द्वारा केशो नाथ (सुप्रा) और केरल राज्य विज्ञान (सुप्रा) के मामलों में पूर्ण पीठ को गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण याचिका का फैसला नहीं करना चाहिए था और डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए संदर्भ का जवाब देने के बाद, इसे माफ कर देना चाहिए था कानून के अनुसार निर्णय के लिए डिवीजन बेंच को पुनरीक्षण याचिका। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन सही प्रतीत होता है।

8. केशो नाथ (सुप्रा) के मामले में, लगभग समान स्थिति में, इस न्यायालय ने यह विचार किया है कि जब एक बड़ी पीठ को संदर्भ दिया जाता है, तो बड़ी पीठ को संदर्भ का उत्तर देना चाहिए और उसके बाद मामले को उचित पीठ को भेज देना चाहिए। गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए उस मामले में भी विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को डिवीजन बेंच को इस सवाल पर भेजा था कि, ‘‘क्या निपटान आयुक्त द्वारा 21 जनवरी, 1963 को दिया गया आदेश अंतिम और वर्तमान अपील में बाध्यकारी था, और यदि हां, तो इसका प्रभाव क्या है, वर्तमान अपील में विवाद के बिंदु पर?" डिवीजन बेंच

ने 7 अप्रैल, 1980 के आदेश द्वारा योग्यता के आधार पर अपील का निपटारा किया और इसे लागत के साथ खारिज कर दिया और माना कि मुख्य निपटान आयुक्त द्वारा दिया गया 21 जनवरी, 1963 का आदेश अंतिम नहीं था और सिविल कार्यवाही में बाध्यकारी नहीं था। जिला किराया और प्रबंध द्वारा जारी 22 सितंबर, 1964 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़े गए 7 जून, 1963 के बिक्री प्रमाण पत्र के तहत अपीलकर्ता को दी गई संपत्ति पर प्रतिवादी द्वारा कोई अतिक्रमण था या नहीं, यह तय करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करें। अधिकारी, शिमला, 25 सितंबर 1955 को आयोजित नीलामी बिक्री के अनुसार।

9. इस न्यायालय ने माना कि यह स्पष्ट है कि चूंकि कानून का केवल उपरोक्त प्रश्न एकल न्यायाधीश द्वारा डिवीजन बेंच को भेजा गया था, इसलिए डिवीजन बेंच को उनके द्वारा संदर्भित कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के बाद मामले को एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय डिवीजन बेंच ने योग्यता के आधार पर दूसरी अपील का निपटारा किया और इसे जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने आगे कहा कि,

> "हमें लगता है कि डिवीजन बेंच ने इस प्रक्रिया का पालन करने में गलती की थी। डिवीजन बेंच को एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित प्रश्न पर उनके द्वारा दिए गए उत्तर के साथ अपील को एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजना चाहिए था और कानून के अनुसार दूसरी अपील का निपटारा करने के लिए इसे एकल न्यायाधीश पर छोड़ दिया गया।"

10. केरल राज्य विज्ञान (सुप्रा) के मामले में भी इस न्यायालय द्वारा यही दृष्टिकोण दोहराया गया था। उस मामले में इस न्यायालय ने पैरा 8 में पहले के निर्णयों का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार कहा,

> "यह काफी अच्छी तरह से तय है कि जब किसी विशिष्ट मुद्दे पर एक विद्वान एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच द्वारा एक बड़ी बेंच को संदर्भ दिया जाता है, यानी, डिवीजन बेंच या पूर्ण बेंच या संविधान पीठ, जैसा भी मामला हो, बड़ी पीठ उस मुद्दे पर निर्णय नहीं दे सकती है जो संदर्भित प्रश्न नहीं है।"

11. मौजूदा मामले में भी, लगभग ऐसी ही स्थिति हुई थी कि केरल उच्च न्यायालय की विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्ण पीठ को एक संदर्भ दिया गया था और पूर्ण पीठ ने संदर्भ का जवाब देने के बाद पुनरीक्षण याचिका पर फैसला किया था। स्वयं गुण-दोष के आधार पर, जिसे करने का पूर्ण पीठ को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि पुनरीक्षण याचिका को निर्णय के लिए पूर्ण पीठ को नहीं भेजा गया था। चूँकि, केवल पूर्ण पीठ को संदर्भित किया गया था, पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था और गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने के लिए मामले को डिवीजन बेंच को भेज देना चाहिए था। नतीजतन, हमने दिनांक 31.1.2003 के आक्षेपित आदेश के उस हिस्से को रद्द कर दिया है जिसके तहत पूर्ण पीठ ने अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम उस मुद्दे के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं जिसे डिवीजन बेंच ने पूर्ण बेंच को भेजा था। हम केवल इस मामले की जांच कर रहे हैं कि क्या पूर्ण पीठ पुनरीक्षण याचिका का निपटारा स्वयं कर सकती थी या नहीं। इन परिस्थितियों में, हम इस अपील को इस हद तक स्वीकार करते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका पर पूर्ण पीठ द्वारा

गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का पूर्ण पीठ का आदेश सही नहीं था। अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसे एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार इसका निपटान करेगी। चूंकि मामला पुराना है, इसलिए हम डिवीजन बेंच से पुनरीक्षण याचिका का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध करते हैं।

12. यहां ऊपर बताए गए आरोप की सीमा तक अपील की अनुमति है। मूल्य के हिसाब से कोई आदेश नहीं।

सिविल अपील संख्या 8422/2001 को खारिज कर दिया गया और सिविल अपील सं. 1817/2004 की अनुमति है।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कुसुम मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।